भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1509

<u>दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

व्यापार घाटा

1509 श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ते आयात के कारण अक्तूबर 2025 में 141% बढ़कर 21.8 बिलियन डॉलर हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 72.9 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष अक्तूबर के 73.4 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा कई देशों की कई बार यात्रा शामिल है, का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है और पिछले कई वर्षों के दौरान निर्यात के रुझान में गिरावट ही आ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान जिन देशों के साथ चर्चा की है और ऐसे देशों की कई यात्राएं की हैं, उनके साथ कुल कितने मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय व्यापार समझौते हस्ताक्षरित या संपन्न हुए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) अक्टूबर 2025 में समग्र व्यापार घाटे में बढ़ोतरी मुख्य रूप से पण्यवस्तु आयात में तीव्र वृद्धि का परिणाम है, जबकि भारत का सेवा क्षेत्र लगातार मज़बूत समर्थन प्रदान कर रहा है। सोने और चांदी की अधिक आवक शिपमेंट की वजह से पण्यवस्तुओं के

आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोने के आयात में वृद्धि का कारण इकाई मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही है। चाँदी के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण चाँदी की

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और फार्मा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक माँग में वृद्धि है। इन कारकों के कारण सामूहिक रूप से व्यापार घाटे में वृद्धि हुई।

(ग) अक्टूबर 2025 में भारत के समग्र निर्यात में कमी आई, जिसका मुख्य कारण पण्यवस्तु निर्यात में अस्थायी गिरावट थी। अक्टूबर 2025 में, पण्यवस्तु निर्यात के आँकड़ों में अक्टूबर 2024 के उच्च आधार के कारण गिरावट आई है, जो अक्टूबर महीनों के पण्यवस्तु निर्यात के लिए सबसे अधिक है। इसके अलावा, अप्रैल-अक्टूबर 2025 की संचयी अवधि में भारत का निर्यात कार्यनिष्पादन 4.1% की मज़बूत वृद्धि दर्ज करते हुए एक सकारात्मक और सुदृढ़ (ट्रजेक्टरी) को दर्शाता है। संचयी आँकड़ों में यह स्थिर वृद्धि भारत के बाह्य क्षेत्र की अंतर्निहित शक्ति और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है, जिससे यह साबित होता है कि यह आगे बढ़ते हुए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम है।

(घ) आज भारत की व्यापार नीति विश्वसनीयता, लचीलेपन और कार्यनीतिक जुड़ाव पर आधारित है। सरकार ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रत्येक उच्च स्तरीय दौरा वास्तविक परिणामों में परिणत हो ।प्रमुख भागीदारों के साथ लगातार बातचीत को आगे बढ़ाया है।

भारत के निर्यात क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में लचीलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक सशक्त संदेश दिया है, और पहली और दूसरी दोनों तिमाही में अब तक का सर्वाधिक तिमाही निर्यात दर्ज किया है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में भारत का निर्यात 418.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2024 की इसी अवधि के 395.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, यह 5.8% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह देश के लिए पहली छमाही का अब तक का उच्चतम निर्यात कार्य-निष्पादन है। ये आंकड़े भारत के निर्यात इकोसिस्टम की निरंतर मजबूती और हाल के वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों के लाभों को दिखाता है, जिनमें लॉजिस्टिक्स में सुधार, बंदरगाह क्षमता में बढ़ोतरी, निर्यात को आसान बनाने के उपाय और उच्च विकास वाले क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहन शामिल हैं।

भारत ने वैश्विक रुझानों से आगे बढ़ने के लिए अपनी विविध निर्यात बास्केट का लाभ उठाया है, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है, और सेवा निर्यात का विस्तार किया है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही की गति और निर्यातकों के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन के साथ, भारत वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि में एक मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है। अब तक का उच्चतम तीमाही और छमाही निर्यात न केवल भारत के लचीलेपन को दर्शाते है, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी साझेदार के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका की भी दर्शाते हैं।

(ङ.) सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ निम्नलिखित 5 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं:

1. भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)
2. भारत-यूएई सीईपीए
3. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत—आस्ट्रेलिया ईसीटीए)
4. भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)
5. भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) (भारत और ब्रिटेन द्वारा पुष्टि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा)

मुक्त व्यापार समझौतों को निरंतर दौर की वार्ताओं और दोनों पक्षकारों के पारस्परिक दौरों के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जिससे भरोसा बनता है, लंबित मुद्दों का समाधान होता है, तथा व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए ठोस परिणाम देते हैं।

*****

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 1509**
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटा

1509 श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ते आयात के कारण अक्तूबर 2025 में 141% बढ़कर 21.8 बिलियन डॉलर हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 72.9 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष अक्तूबर के 73.4 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा कई देशों की कई बार यात्रा शामिल है, का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है और पिछले कई वर्षों के दौरान निर्यात के रुझान में गिरावट ही आ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान जिन देशों के साथ चर्चा की है और ऐसे देशों की कई यात्राएं की हैं, उनके साथ कुल कितने मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय व्यापार समझौते हस्ताक्षरित या संपन्न हुए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) अक्टूबर 2025 में समग्र व्यापार घाटे में बढ़ोतरी मुख्य रूप से पण्यवस्तु आयात में तीव्र वृद्धि का परिणाम है, जबकि भारत का सेवा क्षेत्र लगातार मज़बूत समर्थन प्रदान कर रहा है। सोने और चांदी की अधिक आवक शिपमेंट की वजह से पण्यवस्तुओं के

आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोने के आयात में वृद्धि का कारण इकाई मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही है। चाँदी के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण चाँदी की

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और फार्मा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक माँग में वृद्धि है। इन कारकों के कारण सामूहिक रूप से व्यापार घाटे में वृद्धि हुई।

(ग) अक्टूबर 2025 में भारत के समग्र निर्यात में कमी आई, जिसका मुख्य कारण पण्यवस्तु निर्यात में अस्थायी गिरावट थी। अक्टूबर 2025 में, पण्यवस्तु निर्यात के आँकड़ों में अक्टूबर 2024 के उच्च आधार के कारण गिरावट आई है, जो अक्टूबर महीनों के पण्यवस्तु निर्यात के लिए सबसे अधिक है। इसके अलावा, अप्रैल-अक्टूबर 2025 की संचयी अवधि में भारत का निर्यात कार्यनिष्पादन 4.1% की मज़बूत वृद्धि दर्ज करते हुए एक सकारात्मक और सुदृढ़ (ट्रजेक्टरी) को दर्शाता है। संचयी आँकड़ों में यह स्थिर वृद्धि भारत के बाह्य क्षेत्र की अंतर्निहित शक्ति और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है, जिससे यह साबित होता है कि यह आगे बढ़ते हुए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम है।

(घ) आज भारत की व्यापार नीति विश्वसनीयता, लचीलेपन और कार्यनीतिक जुड़ाव पर आधारित है। सरकार ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रत्येक उच्च स्तरीय दौरा वास्तविक परिणामों में परिणत हो ।प्रमुख भागीदारों के साथ लगातार बातचीत को आगे बढ़ाया है।

भारत के निर्यात क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में लचीलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक सशक्त संदेश दिया है, और पहली और दूसरी दोनों तिमाही में अब तक का सर्वाधिक तिमाही निर्यात दर्ज किया है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में भारत का निर्यात 418.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2024 की इसी अवधि के 395.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, यह 5.8% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह देश के लिए पहली छमाही का अब तक का उच्चतम निर्यात कार्य-निष्पादन है। ये आंकड़े भारत के निर्यात इकोसिस्टम की निरंतर मजबूती और हाल के वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों के लाभों को दिखाता है, जिनमें लॉजिस्टिक्स में सुधार, बंदरगाह क्षमता में बढ़ोतरी, निर्यात को आसान बनाने के उपाय और उच्च विकास वाले क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहन शामिल हैं।

भारत ने वैश्विक रुझानों से आगे बढ़ने के लिए अपनी विविध निर्यात बास्केट का लाभ उठाया है, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है, और सेवा निर्यात का विस्तार किया है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही की गति और निर्यातकों के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन के साथ, भारत वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि में एक मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है। अब तक का उच्चतम तीमाही और छमाही निर्यात न केवल भारत के लचीलेपन को दर्शाते है, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी साझेदार के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका की भी दर्शाते हैं।

(ड.) सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ निम्नलिखित 5 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं:

1. भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)
2. भारत-यूएई सीईपीए
3. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत—आस्ट्रेलिया ईसीटीए)
4. भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)
5. भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) (भारत और ब्रिटेन द्वारा पुष्टि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा)

मुक्त व्यापार समझौतों को निरंतर दौर की वार्ताओं और दोनों पक्षकारों के पारस्परिक दौरों के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जिससे भरोसा बनता है, लंबित मुद्दों का समाधान होता है, तथा व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए ठोस परिणाम देते हैं।

*****